25437 disabled persons in employment.

6. During 1981, a scheme of giving Public Telephone Booths to handicapped individuals to promote employment was launched. Till 31st December, 1981, 978 Public Telephone Booths have been alloted to handicapped people as against a target of 887 for 1981-82.

7. 3 per cent vacancies are resevcd in Group C and D in Government and comparable posts in public sector undertakings for physically handicapped persons. During January-September 1981, 984 persons were given employment in Central Ministries and Undertakings.

16 State Governments have given 2—4 per cent reservation in Group C and D vacancies for physically handicaped persons.

ईश्वर भाई पटेल समीत का प्रीतवेदन

10156. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ईशवर भाई पटेल समिति का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार छठी और सातवीं कक्षाओं में हिन्दी अथवा अंग्रेजी के शिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है;

(ग) क्या उपरोक्त प्रतिवेदन के अनुसार छठी और सातवीं कक्षाओं के क्षात्रों के लिए हिन्दी का अध्ययन वैकल्पिक किया गया है ; और

(घ) क्या पटेल समिति का प्रतिवेदन हिन्दी भाषा को अधिक लोकप्रिय बनाने में सहायक है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और सांस्कृतिक तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमति शीला कौल): (क) डा. ईश्वर भाई जे. पटेल की अध्यक्षता में नियुक्त 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यचार्य से संबंधित समीक्षा सामति की रिपोर्ट पर जुलाई 1978 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया और इसकी सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया ।

(ख) से (घ) ईशवर भाई पटेल समिति ने अध्ययन योजना में शिक्षा अयोग (1964-66) द्वारा पहले से की गयी सिफारिशों के अलावा भाषाओं के स्थान के संबंध में कोई विशेष सिफारिशें नहीं की ।

O.T. Allowance in Madras Division

10157. SHRI M. ARUNACHALAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Maintenance staff in S & T department under CSI/E/MS on Madras Division and staff under CE/Construction working at jolarpet on Madras Division on Southern Railway have been paid overtime arrears as per RLT from 1974;

(b) if so, what are the reasons for not paying such overtime arrears to ELR staff under DSTE/W/YBGM, DSTE/RM/MS who are also eligible for the same arrears; and

(c) whether Government would take immediate action to pay the arrears to ELR under DSTE/W/TBM, DSTE/RM without further delay as they are also eligible for such payment of arrears of Overtime?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : (a) Yes.

(b) and (c). The matter is under review and overtime payments, if any due in thse cases will be arranged early.